

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने तातारस्तान के प्रमुख एच.ई. रुस्तम मिन्निखानोव से की मुलाकात

दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित एआईएम कांग्रेस-2026 में मुख्यमंत्री ने की शिरकत

आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-27 के लिए दिया आमंत्रण

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने तातारस्तान के प्रमुख एच.ई. रुस्तम मिन्निखानोव से की मुलाकात

भोपाल। दुबई विजिट- दूसरा दिन- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दुबई प्रवास के दौरान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित 'एआईएम कांग्रेस-2026' में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने रूसी गणराज्य तातारस्तान के प्रमुख (रईस) महामहिम रुस्तम मिन्निखानोव के साथ उच्चस्तरीय द्विपक्षीय बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य मध्यप्रदेश और तातारस्तान के बीच व्यापार एवं निवेश सहयोग को प्रगाढ़ करना, सेक्टर-विशिष्ट

रणनीतिक साझेदारियों की पहचान करना तथा आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2027 (नवंबर) में तातारस्तान की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने महामहिम रुस्तम मिन्निखानोव को मध्यप्रदेश की समृद्ध औद्योगिक क्षमताओं और निवेश अनुकूल वातावरण से अवगत कराते हुए आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2027 में सम्मिलित होने का औपचारिक निमंत्रण दिया। तातारस्तान के प्रमुख ने इस निमंत्रण का स्वागत करते हुए आश्चर्य व्यक्त किया कि वे एक सशक्त निवेशक प्रतिनिधिमंडल (डेलिगेशन) के साथ समिट में भाग लेंगे तथा राज्य में निवेश की ठोस संभावनाओं को आगे बढ़ाएंगे। बैठक के दौरान दोनों पक्षों के बीच एडवांस्ड मैनुफैक्चरिंग, पेट्रोकेमिकल्स, फूड

प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स, कौशल विकास, कृषि एवं इनोवेशन-आधारित आधुनिक तकनीकों में सहयोग पर विस्तृत विमर्श हुआ। भारत और तातारस्तान के प्रगाढ़ होते आर्थिक संबंधों के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश के साथ बेटुबी और जीटुजी स्तर पर दीर्घकालिक साझेदारी विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया। तातारस्तान की ओर से मुख्यमंत्री डॉ. यादव, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों और राज्य के व्यापारिक प्रतिनिधियों को टाइम: रूस-भारत फोरम तथा संबंधित प्रदर्शनी में सहभागिता के लिये आमंत्रित किया गया। बैठक में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय बिजनेस मिशन आयोजित करने, संयुक्त परियोजनाओं की संभावनाओं को धरातल पर उतारने और त्वरित समन्वय के लिए अधिकृत



नोडल ऑफिसर्स को नामित करने पर भी सहमति व्यक्त की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यूएई के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉ. थानी बिन अहमद जैयौदी के साथ उच्च स्तरीय वन-टू-वन बैठक की। बैठक में दोनों पक्षों के बीच भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के तहत

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यूएई के विदेश व्यापार राज्य मंत्री महामहिम डॉ. थानी बिन अहमद जैयौदी के साथ उच्च स्तरीय वन-टू-वन बैठक की। बैठक में दोनों पक्षों के बीच भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के तहत

गैर-तेल व्यापार, उन्नत प्रौद्योगिकी, सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला और सीमा-पार निवेश को गति देने पर गहन विचार-विमर्श हुआ। मध्यप्रदेश को यूएई निवेशकों के पसंदीदा गंतव्य के रूप में किया पेश मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यूएई के निवेशकों के समक्ष मध्यप्रदेश के निवेश अवसरों और आदर्श निवेश गंतव्य की विशेषताओं से अवगत कराया, जिनमें रणनीतिक केंद्रीय अवस्थिति, प्रतिस्पर्धी लागत, उपलब्ध औद्योगिक भूमि और स्थापित अवसंरचना की प्रमुखता से रखा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश देश के प्रमुख बाजारों तक सीधी और सुगम पहुंच प्रदान करता है। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की उद्योग-हितैषी नीतियों और सिंगल विंडो सुविधा का उल्लेख करते हुए यूएई निवेशकों को

समयबद्ध राज्य-स्तरीय सहायता का पूर्ण भरोसा दिलाया। प्राथमिकता वाले सेक्टरों और खाद्य प्रसंस्करण में साझेदारी का आह्वान बैठक में मध्यप्रदेश में निवेश के विभिन्न अवसरों पर चर्चा हुई, जिनमें विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, नवकरणीय ऊर्जा एवं भंडारण, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रिक वाहन (एव), स्मार्ट विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन और स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने फूड पार्क, मत्स्य पालन एवं एक्वाकल्चर, कोल्ड चेन, हरित ऊर्जा और नियात प्लेटफॉर्म के विकास में यूएई की सक्रिय भागीदारी का आग्रह किया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए दिया न्योता मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने महामहिम डॉ. थानी बिन अहमद

जैयौदी को मध्यप्रदेश में आयोजित होने वाले आगामी 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2027' में शामिल होने का औपचारिक आमंत्रण दिया। यूएई के विदेश व्यापार राज्य मंत्री ने इस आमंत्रण को स्वीकारते हुए आश्चर्य व्यक्त किया कि वे यूएई के प्रमुख निवेशकों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल (डेलिगेशन) के साथ सहभागिता करेंगे। अगला कदम: 3 माह में समीक्षा और नोडल ऑफिसर की नियुक्ति द्विपक्षीय संबंधों और औद्योगिक साझेदारी को व्यावहारिक रूप देने के लिए 5 से 10 क्रियान्वयन-तैयार परियोजनाओं की पहचान करने और संयुक्त समीक्षा व्यवस्था स्थापित करने पर सहमति हुई। इसके तहत 'मध्यप्रदेश-यूएई इन्वेस्टमेंट राउंड टेबल' का आयोजन किया जाएगा।

ईरान युद्ध और महंगाई ने बढ़ाई मुश्किल ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन

मिडटर्म चुनाव में डेमोक्रेट्स की होगी जीत



रिपब्लिकन पार्टी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कई चुनावी क्षेत्रों में उम्मीदवारों को ट्रंप की लोकप्रियता का फायदा मिलने के बजाय उनसे दूरी बनाने की जरूरत महसूस हो रही है।

वॉशिंगटन। अमेरिका में नवंबर में होने वाले मिडटर्म चुनाव अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए सिर्फ काग्रेस की सीटों का मुकाबला नहीं रह गए हैं। चुनावी माहौल तेजी से ट्रंप के दो साल के शासन पर जनमत संग्रह में बदलता दिखाई दे रहा है। ताजा चुनावी गणित में डेमोक्रेट्स के सदन में बहुमत हासिल करने की संभावना मजबूत हुई है। एक ताजा विश्लेषण के मुताबिक मौजूदा रूझान जारी रहे तो डेमोक्रेट्स 221 सीटों तक पहुंच सकते हैं, जबकि

असली लड़ाई नवंबर से पहले की आखिरी दौड़ में फिलहाल चुनावी तस्वीर को ट्रंप की हार तय कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन संकेत साफ हैं कि रिपब्लिकन के लिए यह आसान चुनाव नहीं रहने वाला। एक तरफ ट्रंप की कमजोर होती लोकप्रियता, महंगाई और ईरान युद्ध हैं, दूसरी तरफ रिपब्लिकन के पास मजबूत फंडिंग, चुनावी परिसीमन और ट्रंप का बड़ा समर्थक आधार है। यही वजह है कि नवंबर का मिडटर्म चुनाव अब सिर्फ डेमोक्रेट्स बनाम रिपब्लिकन नहीं, बल्कि काफी हद तक ट्रंप के पक्ष या खिलाफ जनमत में बदलता जा रहा है।

रिपब्लिकन करीब 214 सीटों पर रह सकते हैं। हालांकि यह चुनाव का अंतिम अनुमान नहीं है। रिपब्लिकन के लिए बेहतर स्थिति में तस्वीर पूरी तरह उलट भी सकती है। रिपब्लिकन पार्टी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कई चुनावी क्षेत्रों में उम्मीदवारों को ट्रंप की लोकप्रियता का फायदा मिलने के बजाय उनसे दूरी बनाने की जरूरत महसूस हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ रिपब्लिकन रणनीतिकार मान रहे हैं कि ट्रंप को केंद्र में रखकर चुनाव

लड़ें। पार्टी के लिए जोखिम बढ़ा सकता है। इसके बावजूद पार्टी के पास उनसे पूरी तरह अलग होने का विकल्प भी मौजूद है, क्योंकि ट्रंप के समर्थकों को मतदान केंद्र तक लाना जीओपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। **ईरान युद्ध ने बिगाड़ा चुनावी गणित**- ट्रंप के लिए ईरान युद्ध सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौतियां में शामिल हो गया है। लंबे खिंचते संघर्ष के साथ तेल की कीमतों और महंगाई का दबाव बढ़ा है। इससे विदेशी नीति का मुद्दा सीधे अमेरिकी

महंगाई भी ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी चुनावों में अर्थव्यवस्था हमेशा निर्णायक मुद्दा रही है। इस बार भी यही मुद्दा ट्रंप प्रशासन के लिए चुनौती बन रहा है। महंगाई और रोजगारों की बढ़ती लागत को लेकर मतदाताओं की नाराजगी डेमोक्रेट्स को मौका दे रही है। सर्वे के मुताबिक आर्थिक असंतोष रिपब्लिकन की मामूली कांग्रेस बहुमत को खत्म करने में डेमोक्रेट्स की मदद कर सकता है। फिलहाल कहानी एकतरफा नहीं है। रिपब्लिकन ने कई राज्यों में चुनावी परिसीमन के जरिए सदन की सीटों का गणित अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। इसके अलावा रिपब्लिकन के पास बड़ा चुनावी फंड भी है और ट्रंप खुद कई अहम सीटों पर प्रचार कर रहे हैं। पार्टी की रणनीति का बड़ा हिस्सा अपने समर्थकों को बड़ी संख्या में मतदान के लिए निकालने पर टिका है।

मतदाताओं की जेब से जुड़ गया है। ताजा रिपोर्टों के मुताबिक ईरान संघर्ष के कारण तेल की कीमतें करीब 95 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंची हैं और महंगाई को लेकर अमेरिकी परिवारों की चिंता बढ़ी है। ईरान युद्ध और ऊंची कीमतों ने रिपब्लिकन आधार में असंतोष बढ़ाया है।

दिल्ली हॉस्टल हादसे में सिस्टम पर हाईकोर्ट सख्त

7 मौतों के लिए नगर निगम जिम्मेदार



नई दिल्ली। दिल्ली के सत्य निकेतन में हॉस्टल की इमारत गिरने के हादसे ने सिर्फ जर्जर भवनों की स्थिति ही नहीं, बल्कि उनकी निगरानी करने वाली सरकारी एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने हादसे के लिए दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विश्वविद्यालय को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि बाहर से पढ़ने आने वाले छात्रों के हॉस्टलों की स्थिति पर चिंता जताई। कोर्ट की टिप्पणी से साफ है कि मामला सिर्फ एक इमारत के गिरने तक सीमित नहीं है। छात्रों के रहने के लिए इस्तेमाल हो रही इमारतों की सरकार, केंद्र सरकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और दिल्ली विश्वविद्यालय को 10 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस बीच पुलिस ने हॉस्टल के मालिक हरिराम बंसल को राजस्थान के पिवाड़ी से हिरासत में लिया है। पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट

नोटिस जारी किया था। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 12 लोगों को मलबे से बचाया गया, जिनमें 5 की हालत गंभीर बताई गई है। करीब 27 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सोमवार शाम 4:30 बजे बचाव अभियान पूरा कर लिया गया। हॉस्टलों की हालत बेहद खराब अदालत ने दिल्ली में बाहर से पढ़ने आने वाले छात्रों के लिए उपलब्ध हॉस्टलों की स्थिति पर चिंता जताई। कोर्ट की टिप्पणी से साफ है कि मामला सिर्फ एक इमारत के गिरने तक सीमित नहीं है। छात्रों के रहने के लिए इस्तेमाल हो रही इमारतों की सरकार, केंद्र सरकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और दिल्ली विश्वविद्यालय को 10 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस बीच पुलिस ने हॉस्टल के मालिक हरिराम बंसल को राजस्थान के पिवाड़ी से हिरासत में लिया है। पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट

श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलटी, 13 की मौत

बागपत। यूपी के बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलट गई। हादसे में 7 साल के बच्चे समेत 13 लोगों की मौत हो गई। 19 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पिकअप में सवार 32 श्रद्धालु राजस्थान के बागड़ धाम (गोगामेड़ी) से बदायूं लौट रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रिविंजर देर रात करीब 1 बजे पिकअप को एक तेज रफ्तार केक्टर ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद पिकअप बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। फिर करीब 10 फीट तक फिसलते हुए सड़क के बीचों-बीच पलट गई। 50 मीटर दूर तक लाशें बिखर गईं। हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई। घायल श्रद्धालु दर्द से कराहने लगे। धमाके जैसी आवाज सुनकर आसपास के लोग भागकर मौके पर पहुंचे।

महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर-4 की तैयारी की सुगबुगाहट

मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ी सियासी तोड़-फोड़ की पटकथा लिखी जा रही है। शिवसेना शिंदे गुट के विधायक मुरजी पटेल ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में राज्य में ऑपरेशन टाइगर-4 होने वाला है। पटेल का कहना है कि शिवसेना ठाकरे गुट के करीब 14 विधायक एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लोकसभा में कुल 9 सांसदों में से 6 सांसद पार्टी से अलग होकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए थे। लोकसभा में अब शिंदे के सांसदों की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। हालांकि, 14 विधायकों वाली बात को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। मुरजी पटेल के दावे के मुताबिक, ठाकरे गुट के सांसदों के बाद अब विधायक और फिर नगरसेवक भी शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। इस पूरी चर्चा में 14 का आंकड़ा बेहद अहम माना जा रहा है। विधानसभा में ठाकरे गुट के पास 20 विधायक हैं। कानून के मुताबिक, अगर इनमें से दो-तिहाई विधायक एक साथ दलबदल करते हैं, तो दलबदल विरोधी कानून के तहत अलग कानूनी और राजनीतिक स्थिति बन सकती है। सूत्रों के हवाले से यह भी दावा किया जा रहा है।

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026: टॉप 5 में एमपी के तीन शहर शामिल, लखनऊ बना देश का सबसे स्वच्छ शहर

इंदौर दूसरे, जबलपुर तीसरे, भोपाल चौथे स्थान पर रहा

इस कैटेगरी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ने 189 अंकों के साथ छठा स्थान प्राप्त किया है।



नई दिल्ली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इस बार देश की सबसे स्वच्छ हवा वाले बड़े शहरों की सूची में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ने बाजी मारी है। लखनऊ को 198 अंकों के साथ पहला स्थान मिला है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर शामिल हैं, में

स्थान मिला है, जो आगरा के साथ संयुक्त रूप से है। इस कैटेगरी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ने 189 अंकों के साथ छठा स्थान प्राप्त किया है। दुर्ग-भिलाई 175.3 अंकों के साथ

17वें स्थान पर रहा। दिल्ली को इस सूची में 172 अंकों के साथ 21वां और मुंबई को 160.8 अंकों के साथ 28वां स्थान मिला है। वहीं 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहर हैं, में ओडिशा के

राउरकेला ने 198.5 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया। दूसरे स्थान पर फिरोजाबाद और गुंटूर 195 अंकों के साथ रहे। इस कैटेगरी में छत्तीसगढ़ के कोरबा ने 186.5 अंकों के साथ

10वां स्थान हासिल किया है। मध्यप्रदेश से ग्वालियर 157 अंकों के साथ 30वें, सागर 178 अंकों के साथ 18वें और उज्जैन 181.5 अंकों के साथ 13वें स्थान पर रहा।

सड़क हादसे में मारे गए युवक के परिजन ने साथी पर लगाए हत्या के आरोप



गाजियाबाद: गाजियाबाद के लोनी इलाके की एक कॉलोनी में रहने वाली दो नाबालिग छात्राओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वारदात को अंजाम देने वाले दूसरे समुदाय के दोनों फरार आरोपियों को पुलिस ने रविवार देर रात हुई मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र के एक निवासी ने पुलिस को बताया कि उनकी 15 वर्षीय बेटी कक्षा 8वीं क्लास की छात्रा है। वह और उनकी पत्नी मजदूरी कर परिवार का गुजारा करते हैं। उनकी बेटी 2 सितंबर की देर शाम घर से लापता हो गई थी। कुछ देर बाद पता चला कि 7वीं क्लास में पढ़ने वाली उनकी बेटी को एक सहेली भी घर पर नहीं है। 3 सितंबर की सुबह किसी तरह दोनों किशोरियां घर पहुंचीं। उन्होंने परिजनों को बताया कि कॉलोनी में रहने वाले दूसरे समुदाय के दो युवक उन्हें जबनर अपने साथ एक घर में ले गए और उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद छात्राओं के परिजन दोनों किशोरियों को लेकर थाने पहुंचे। पुलिस ने छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कर दोनों किशोरियों को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया। जांच में दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने छेड़खानी के मुकदमे में सामूहिक दुष्कर्म और पोक्सो ऐक्ट की धाराएं बढ़ा दीं।



नोएडा में तेज आवाज में गाना

बजाने से रोका तो पीट-पीटकर

मार डाला, पार्टी यू ही चलती रही

नोएडा: गेझा गांव में शनिवार को जन्मदिन के दौरान तेज आवाज में गाने बजाने का विरोध करने पर दो युवकों ने पड़ोसी को पीट दिया। परिजन घायल को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फेज-2 थाने की पुलिस ने दोनों आरोपी भाइयों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एसीपी दीक्षा सिंह ने कहा कि घटना के आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया। आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है, ताकि घटना के संबंध में अहम साक्ष्य जुटाए जा सकें। पुलिस के अनुसार गेझा गांव की गली नंबर पांच में सतीश शर्मा परिवार के साथ रहते थे। वह किराये पर मकान दिलाने का काम करते थे। उनके घर के सामने सुमित अपने पिता सतीश और भाई ललित के साथ रहता है। शनिवार को सुमित के बेटे का जन्मदिन था। घर में समारोह चल रहा था और तेज आवाज में गाने बज रहे थे। आवाज से परेशान सतीश शर्मा ने कई बार गाने की आवाज कम करने के लिए कहा। जब आवाज कम नहीं हुई तो शाम करीब सात बजे वह सुमित के घर पहुंचे और फिर से आपत्ति जताई। इसी दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई।

खुले सीवर मेनहोल से हादसे का खतरा

ट्रांस हिंडन। वैशाली सेक्टर-3 के एक ब्लॉक रेजिडेंसी वेलफेयर एसोसिएशन क्षेत्र में तीन दिन से सीवर के ढक्कन खुले पड़े हैं। इससे स्थानीय लोगों में हादसे का डर बना हुआ है। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष धीरेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि करीब तीन दिन पहले नगर निगम की टीम ने सफाई के लिए सीवर के ढक्कन हटाए थे। इसके बाद न तो सफाई का काम पूरा किया गया और न ही खुले मेनहोल को बंद किया गया। उन्होंने बताया कि आसपास से बड़ी संख्या में लोग आते-जाते हैं। ऐसे में खुले सीवर में किसी के गिरने की आशंका बनी हुई है।

दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाना का जागरूकता अभियान शुरू, मार्च 2027 तक चलेगा : सिरसा

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करने और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए निरंतर और व्यापक प्रयास कर रही है। इन प्रयासों में प्रवर्तन, तकनीकी हस्तक्षेप, हितधारकों की भागीदारी और जनसहभागिता को समाहित किया गया है। इसी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार ने एक व्यापक शहरव्यापी सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) एवं जागरूकता अभियान शुरू किया है।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज एक विज्ञापि जारी करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण की चुनौती से निपटने के लिए पूरी गंभीरता और निरंतरता के साथ कार्य कर रही है। सरकार हर स्तर पर प्रवर्तन को मजबूत कर रही है और व्यापक उपाय लागू कर रही है। लेकिन स्वच्छ हवा की लड़ाई केवल सरकार के प्रयासों से नहीं जीती जा सकती। प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक संस्थान और प्रत्येक हितधारक की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है।

सिरसा ने बताया कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) द्वारा संचालित यह अभियान सितंबर 2026 से मार्च 2027 तक 'साथ निभाएं, प्रदूषण घटाएं' थीम के तहत चलाया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से दिल्ली के विभिन्न सरकारी विभागों, संस्थानों, उद्योगों, समुदायों और नागरिकों को एकजुट करते हुए स्वच्छ और स्वस्थ वायु के लिए एक निरंतर एवं सामूहिक जनआंदोलन तैयार किया जाएगा।

इसी उद्देश्य से यह अभियान पर्यावरण संबंधी जागरूकता को केवल जानकारी तक सीमित न रखते हुए उसे कार्रवाई में बदलने पर जोर देगा। इसके माध्यम से

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत

सिंह संधू ने कहा कि देश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखना केवल कलाकारों और सांस्कृतिक संस्थानों की जिम्मेदारी नहीं है। परिवार, शिक्षण संस्थान, नागरिक समाज और कॉर्पोरेट जगत को भी इसमें सक्रिय भागीदारी निभानी होगी। एलजी ने यह बात रविवार को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के मल्टीपर्पज हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में कही। समारोह में उन्होंने भारतीय कला और सांस्कृतिक परंपराओं में योगदान देने वाले पांच दिग्गज कलाकारों गुरु वीपी धनंजयन और गुरु शांता धनंजयन को भरतनाट्यम में योगदान, उस्ताद शाहिद परवेज खान को सितार और हिंदुस्तानी



शास्त्रीय संगीत, टीएच विनायकराम को कर्नाटक शास्त्रीय संगीत, मार्गी मधु को भारतीय रंगमंच परंपरा तथा केएस राधाकृष्णन को भारतीय मूर्तिकला में योगदान के लिए लेजेंड्स ऑफ इंडिया लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया।

उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि इन कलाकारों का सम्मान केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों का अभिनंदन नहीं है, बल्कि उस सभ्यतागत विरासत का सम्मान है, जिसे उन्होंने दशकों की साधना, अनुशासन और समर्पण से जीवित रखा है। भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य, रंगमंच और दृश्य कलाएं देश के इतिहास, कल्पना और सामूहिक स्मृति की महत्वपूर्ण धरोहर हैं। ये

कला परंपराएं भाषा और क्षेत्र की सीमाओं से परे लोगों को जोड़ने का काम करती हैं।

एलजी ने कहा कि तकनीक के तेजी से बदलते दौर में सांस्कृतिक परंपराओं को बचाए रखना पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। हालांकि, संस्कृति का संरक्षण करने का मतलब उसे अतीत में स्थिर कर देना नहीं है। जरूरी है कि परंपराओं को नई पीढ़ी के लिए प्रासंगिक बनाया जाए और युवाओं को उन्हें समझने, सीखने तथा नाए सदस्यों में आगे बढ़ाने के अवसर दिए जाएं। उन्होंने शक्ति की सतधाया के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत की प्रगति केवल आर्थिक और तकनीकी विकास तक सीमित नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने शालीमार बाग विधानसभा में कई परियोजनाओं का किया शुभारंभ

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को शालीमार बाग विधानसभा में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था, पार्कों के सौंदर्यीकरण और सड़क कनेक्टिविटी को और मजबूती मिलेगी।

शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री ने शालीमार बाग स्थित बीबी-ब्लॉक की स्कूल बिल्डिंग के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। इससे क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए बेहतर शैक्षणिक सुविधाओं के विकास को गति मिलेगी।

वहीं, विद्युत व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए एएफ-ब्लॉक में खुले ओवरहेड कंडक्टर को अंडरग्राउंड केबल में बदलने के कार्य का शुभारंभ किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने शालीमार बाग के सीएंडडी ब्लॉक की मेन रोड पर खुले ओवरहेड कंडक्टर को अंडरग्राउंड केबल में बदलने के कार्य का शुभारंभ किया। इससे क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी।



मुख्यमंत्री ने पीतमपुरा स्थित श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज से रिंग रोड तक नई सड़क के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ किया। साथ ही पीतमपुरा के एसपी-टीपी लगभग 2.84 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह सड़क क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के साथ-साथ नागरिकों के

आवागमन को अधिक सुविधाजनक बनाएगी। उन्होंने हैदरपुर के नेहरू कैप में नवनिर्मित टॉयलेट ब्लॉक का भी उद्घाटन किया। साथ ही पीतमपुरा के एसपी-टीपी ब्लॉक में आधुनिक कॉम्पेक्टर का उद्घाटन किया। आधुनिक कचरा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में यह पहल क्षेत्र में

दिल्ली के जाफराबाद में अवैध शराब के गोदाम पर छापा, 1,576 क्वार्टर बरामद, आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में स्पेशल स्टाफ/एनईडी की टीम ने छापेमारी कर अवैध शराब सप्लायर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1,576 क्वार्टर बोतलें अवैध शराब बरामद की हैं। शराब की बरामद बोतलों पर 'केवल हरियाणा में बिक्री के लिए' लिखा हुआ है।

पुलिस के अनुसार 4 और 5 सितंबर 2026 की दरम्यानी रात स्पेशल स्टाफ/एनईडी को सूचना मिली थी कि जफराबाद इलाके में एक गोदाम में अवैध शराब का भंडारण किया गया है। सूचना के आधार पर एसीपी/ऑपरेशन्स की निगरानी में और इंस्पेक्टर अरविंद सिंह, आईसी/स्पेशल स्टाफ के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने जाफराबाद स्थित सब्जी मंडी प्राइमरी स्कूल के पास जम्मू मोहल्ला में 158/2 नंबर के गोदाम पर छापा मारा।

छापेमारी के दौरान पुलिस टीम को गोदाम से 32 कार्टन मिले। इन कार्टनों की जांच करने पर इनमें कुल 1,576 क्वार्टर बोतलें बरामद हुईं। इन्हें दिल्ली में बेचने की योजना थी, जबकि शराब दिल्ली में बिक्री के लिए अधिकृत नहीं है।

कार्रवाई के दौरान गोदाम के मालिक दीपक



उर्फ छापा को गिरफ्तार किया गया। आरोपी की उम्र 28 वर्ष है और वह बाबरपुर (दिल्ली) का रहने वाला है। बरामद शराब को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

मामले में जाफराबाद थाना पुलिस ने दिल्ली आबकारी अधिनियम की धारा 33 के तहत एफआईआर दर्ज की है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी शराब कहाँ से लाता था और इसे दिल्ली में किन लोगों तक पहुंचाया जाना था।

जांच के दौरान पुलिस को आरोपी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की भी जानकारी मिली। पुलिस के अनुसार, दीपक उर्फ छापा के खिलाफ डकैती, चोरी, झपटमारी, आबकारी अधिनियम, जुआ अधिनियम और शस्त्र अधिनियम से जुड़े 17 मामले दर्ज रहे हैं।

पुलिस ने उसे थाना वेलकम का बैड कैरेक्टर भी बताया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर अवैध शराब की सप्लाई से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका का पता लगाने में जुटी है।

दिल्ली स्टार्टअप और इनव्यूबेशन नीति 2026 को मिले उद्योग जगत के सुझाव; 10,000 स्टार्टअप और 4 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी को देश के प्रमुख स्टार्ट-अप केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए स्टार्ट-अप संस्थापकों, उद्यमियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने रविवार को आयोजित बैठक में स्टार्ट-अप और इनव्यूबेशन नीति 2026 के क्रियान्वयन को लेकर सुझाव लिए और नीति को और अधिक प्रभावी बनाने पर चर्चा की।

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के युवाओं से किया गया वादा अब धरातल पर उतरता दिखाई दे रहा है।

उन्होंने कहा, 'दिल्ली स्टार्ट-अप और इनव्यूबेशन नीति 2026 के तहत विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों में स्टार्ट-अप के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित करने तथा इनव्यूबेशन केंद्र स्थापित करने की दिशा में सरकार ने ठोस रोलैप तैयार किया है। देशभर से आए प्रमुख स्टार्ट-अप संस्थापकों, सीईओ और उद्योग प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव और सुझाव साझा किए हैं, जिससे नीति को और अधिक व्यावहारिक, प्रभावी तथा स्टार्ट-अप-अनुकूल बनाया जा सकेगा।' मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य केवल नई कंपनियों को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ऐसे वातावरण तैयार करना है जहां युवा



नवाचार, उद्यमिता और रोजगार सृजन के माध्यम से देश के आर्थिक विकास में योगदान दे सकें। उन्होंने भरोसा जताया कि उद्योग जगत की भागीदारी से तैयार की जाने वाली नीतियां स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को नई गति देंगी। वहीं, दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार स्टार्ट-अप और इनव्यूबेशन नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उद्योग जगत के साथ लगातार संवाद कर रही है। उन्होंने बताया कि इस बैठक का उद्देश्य उन उद्यमियों के अनुभवों को समझना था, जिन्होंने दिल्ली में अपने व्यवसाय की शुरुआत की और उसे सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का विजन

अपने कार्यकाल के दौरान 10,000 से अधिक स्टार्ट-अप को समर्थन और प्रोत्साहन देना है, और इसके माध्यम से युवाओं के लिए 4 लाख से अधिक रोजगार अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि स्टार्ट-अप संस्कृति को बढ़ावा देने से न केवल रोजगार बढ़ेगा, बल्कि नवाचार-आधारित आर्थिक विकास को भी मजबूती मिलेगी। इस दौरान, ज़िप इलेक्ट्रिक के सह-संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी आकाश गुप्ता ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार का यह प्रयास राजधानी को देश की स्टार्ट-अप राजधानी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

» सोनम स्वाति

ग्रेटर नोएडा से Carrefour का भारत में सफर शुरू, 50,000+ वर्ग फुट के फ्लैगशिप स्टोर के साथ उत्तर भारत में विस्तार की तैयारी

नोएडा, 3 सितंबर 2026: प्रमुख फैशन और लाइफस्टाइल रिटेल समूह Apparel Group ने भारत में दुनिया के प्रसिद्ध रिटेल ब्रांड Carrefour के प्रवेश की घोषणा की है। Carrefour का पहला फ्लैगशिप स्टोर H&S Mall, Boulevard Walk, Greater Noida West में शुरू किया गया है।

इसे भारत जैसे तेजी से बढ़ते उपभोक्ता बाजार में दोनों कंपनियों के लिए एक नए और महत्वाकांक्षी अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है। यह लॉन्च Apparel Group की भारत में विकास यात्रा और फूड एवं हाइपरमार्केट रिटेल क्षेत्र में उसके विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। Carrefour की



अंतरराष्ट्रीय रिटेल विशेषज्ञता और Apparel Group की भारतीय बाजार की गहरी समझ को एक साथ लाकर आधुनिक रिटेल का ऐसा मॉडल तैयार करने का लक्ष्य है, जो गुणवत्ता, बेहतर कीमत, सुविधा और भारतीय उपभोक्ताओं की बदलती जरूरतों पर केंद्रित हो। 50,000+ वर्गफुट में पहला फ्लैगशिप स्टोर ग्रेटर नोएडा का यह फ्लैगशिप स्टोर 50,000+ वर्ग फुट में फैला है और

इसमें 15,000+ SKU (उत्पाद विकल्प) उपलब्ध हैं। स्टोर में अंतरराष्ट्रीय स्तर के विशेष उत्पादों के साथ-साथ भारत से प्राप्त स्थानीय उत्पाद भी शामिल हैं। ग्राहकों को यहां ताजे फल-सब्जियां, किराना, बेकरी, घरेलू जरूरतों का सामान, पर्सनल केयर उत्पाद और कई अन्य श्रेणियों के उत्पाद उपलब्ध होंगे। उत्तर भारत में बड़े विस्तार की तैयारी यह स्टोर केवल शुरुआत है।

एयरोसिटी टाउनशिप 231 हेक्टेयर में बसेगी, GDA लेगा इन गांवों की जमीन, क्या है पूरा प्लान

गाजियाबाद: जीडीए की राजनगर एक्सटेंशन के तीन गांवों की जमीन पर एयरोसिटी बसाई जाने की योजना है। इसे परवान चढ़ाने के लिए जीडीए ने 231.3710 हेक्टेयर जमीन चिह्नित कर ली है। साथ ही प्राधिकरण ने रविवार को किसानों और जमीन मालिकों से आपत्ति भी मांगी है। 15 दिन के भीतर जीडीए के नवयुग मार्केट स्थित कार्यालय में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। यदि कोई आपत्ति आती है, तो प्राधिकरण की टीम उसका निस्तारण करेगी। इसके बाद जमीन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

वहीं, अब चिह्नित जमीन को यदि कोई खरीदता है, तो उसे अवैध माना जाएगा। जीडीए अधिकारी बताते हैं कि इस टाउनशिप के लिए अटोर, मोरटी और मेवला अग्रगी गांव की जमीन लेंगे। जमीन लेने के लिए प्राधिकरण 2,831 करोड़ रुपये खर्च करेगा। एयरोसिटी पूरी तरह से कर्मशायल टाउनशिप होगी। यहां कई बड़ी कंपनियों के ऑफिस, होटल, रेस्तरां, मॉल, कॉलेज, स्पोर्ट्स क्लब, स्पोर्ट्स एकेडमी, गोल्फ कोर्स, दुकान, शोरूम आदि के लिए प्लॉट काटे जाएंगे।



संक्षिप्त समाचार

राजस्थान के लिए गौरव का क्षण

शेखावाटी की 14 ऐतिहासिक हवेलियां यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल



जयपुर, एजेंसी। राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र के तीन जिलों सीकर, चूरू और झुंझुन की ऐतिहासिक हवेलियों को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। सूची में शामिल इन हवेलियों को भविष्य में यूनेस्को वर्ल्ड हैरिटेज साइट का दर्जा दिलवाने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। भित्ति चित्रों से सजी, अनेकों वास्तुकला, कलात्मक शैली एवं दीवारों पर उकेरी गई कलाकारी के कारण शेखावाटी की हवेलियां देश-विदेश में प्रसिद्ध है। इनमें अधिकांश हवेलियां 100 वर्ष से अधिक पुरानी है। तीनों जिलों के जिन कस्बों की हवेलियों को सूची में शामिल किया गया है उनमें डूंडलोद, फतेहपुर, अलसीसर, बिसाऊ, चूरू, झुंझुन, खेतड़ी, लक्ष्मणगढ़, नवलगढ़, मंडावा, महनसर, रामगढ़ और सीकर शामिल है। राज्य की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा, कि हवेलियों की दीवारों पर बने चित्र उस समय के सामाजिक जीवन, संस्कृति, परम्पराओं और कलात्मक शैली से रूबरू करवाते हैं।

शिमला में गहराया पेयजल संकट, बूंद-बूंद के लिए तरस रहे लोग
भाजपा ने सरकार और निगम को घेरा



शिमला, एजेंसी। भाजपा प्रदेश मीडिया संयोजक कर्ण नंदा ने राजधानी शिमला में गहराते पेयजल संकट को लेकर कांग्रेस सरकार और नगर निगम शिमला पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि शिमला शहर से पीने का पानी गाबव है और जनता पानी के लिए तरस रही है। कई क्षेत्रों में लोगों को पानी के लिए कई-कई दिन इंतजार करना पड़ रहा है। जिस राजधानी में सरकार 24 घंटे पानी देने के सपने दिखाती रही, वहां आज लोगों के सामने अपने रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए पर्याप्त पानी जुटाना चुनौती बन गया है। कर्ण नंदा ने कहा कि लगभग 972 करोड़ रुपये की 24म7 पेयजल योजना को शिमला की पानी की समस्या का स्थायी समाधान बताकर बड़े-बड़े दावे किए गए थे, लेकिन आज उसी योजना के काम में अनियमितताओं की आशंका के चलते मुख्यमंत्री कार्यालय को जांच के आदेश देने पड़े हैं। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि इतने बड़े प्रोजेक्ट की निगरानी समय रहते क्यों नहीं की गई और जनता को पानी उपलब्ध करवाने के बजाय योजना जांच के घेरे में कैसे पहुंच गई। इसके तहत 5,500 कनेक्शन दिए जाने थे, लेकिन नई लाइन से अभी तक एक भी कनेक्शन नहीं दिया गया। 19 टैंक बनने थे, लेकिन एक भी टैंक तैयार नहीं हुआ। 136 किलोमीटर लंबी लाइन में केवल 51 किलोमीटर लाइन बिछ पाई है और 27 किलोमीटर फीडर में से मात्र 5 किलोमीटर का कार्य हुआ है। नॉन-रेवेन्यू वाटर पर शुन्य प्रतिशत काम और क्लोरीनेशन को लेकर भी काम नहीं होने की बात सामने आई है। ये तथ्य योजना की गति और क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। कर्ण नंदा ने कहा कि एक तरफ शिमला की जनता बूंद-बूंद पानी के लिए परेशान है और दूसरी तरफ करोड़ों रुपये की पेयजल योजना अधूरी पड़ी है। कांग्रेस सरकार और नगर निगम केवल बहाने बनाकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। राजधानी में लोगों को चौथे दिन तक पानी मिलने की स्थिति यदि पैदा हो रही है तो सरकार के 24घंटे पानी के दावे अपने आप सवालों के घेरे में आ जाते हैं।

जिस बेटे का कर दिया था ‘ अंतिम संस्कार ’, वह पंजाब की जेल में मिला जिंदा

कपूरथला, एजेंसी। पंजाब के कपूरथला से एक हरात करने वाली घटना सामने आई है, जिसमें अंतिम संस्कार के बाद एक परिवार को उनका बेटा जिंदा मिल गया। इस कॉल से पता चला कि जिस युवक को परिवार ने मृत मान लिया था, वह असल में जीवित था और जेल में बंद था। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, रवि कुमार नाम के इस युवक के परिवार को उसके जीवित होने का पता तब चला जब उन्हें जेल से एक फोन कॉल आया। यह कॉल उस घटना के बाद आया, जब परिवार ने एक शव का अंतिम संस्कार कर दिया था, जिसे वे अपना लापता बेटे का शव समझ रहे थे। शुरुआती जानकारी के अनुसार रवि कुमार 5 अगस्त को घर से निकला था और लौटा नहीं।

इसरो के निजीकरण पर 9 कर्मचारी यूनियनों ने लिखी चिट्ठी, पूछा- क्या हम सिर्फ रिसर्च करेंगे

बेंगलुरु, एजेंसी। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने के सरकार के फैसले के छह साल बाद पहली बार, इसरो केंद्रों के नौ कर्मचारी संघों ने इस बदलाव की दिशा और इसके आधार को लेकर औपचारिक रूप से चिंता जाहिर की है। अंतरिक्ष विभाग के तहत हजारों कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले इन संघों ने अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष से इस मुद्दे पर लिखित स्पष्टीकरण मांगा है, जो षष्ठ्य के सचिव और इसरो अध्यक्ष भी हैं। 4 सितंबर को सौंपे गए मांग पत्र में कर्मचारी संघों ने कहा कि तय व्यावसायिक गतिविधियों में निजी भागीदारी एक मजबूत और सार्वजनिक स्वामित्व वाले इसरो के साथ सह-अस्तित्व में रह सकती है। लेकिन बिना किसी चर्चा के ऐसी नीति को स्वीकार नहीं किया जा सकता, जो इसरो को केवल एक ऋष्ट बुटीक यानी रिसर्च और डेवलपमेंट तक सीमित बना दे और देश के लॉन्च वाहनों का निर्माण और संचालन सार्वजनिक हाथों से बाहर चला जाए। कर्मचारियों ने इसरो द्वारा विकसित तकनीक को



राष्ट्रीय संपत्ति बताते हुए कहा कि इसका हस्तांतरण पारदर्शी, जवाबदेह और रणनीतिक सुरक्षा और रोजगार के हितों के अनुकूल होना चाहिए। इस संयुक्त ज्ञापन पर इसरो स्टाफ एसोसिएशन स्मार्क एम्प्लॉइज एसोसिएशन, एम्प्लॉइज एसोसिएशन सहित नौ प्रमुख संगठनों

ने हस्ताक्षर किए हैं। कर्मचारी संघों ने इन-स्पेस के अध्यक्ष पवन गोयनका के हालिया सार्वजनिक बयान का भी जिक्र किया, जिसमें कथित तौर पर कहा गया था कि इसरो अंततः किसी भी लॉन्च वाहन का निर्माण नहीं करेगा। संघों ने सवाल पूछा है कि क्या गोयनका का

बयान भारत सरकार, अंतरिक्ष आयोग या अंतरिक्ष विभाग का स्वीकृत निर्णय है? यदि हां, तो इस नीतिगत फैसले की तारीख और भविष्य की भूमिका को लेकर भी स्पष्टता मांगी आधिकारिक जानकारी साझा की जानी चाहिए।

नई भर्तियों पर संकट की आशंका

कर्मचारियों ने करदाताओं के पैसे और पीढ़ियों की मेहनत से तैयार की गई तकनीक, परीक्षण सुविधाओं और लॉन्च कॉम्प्लेक्स को निजी ऑपरेटरों को सौंपने की प्रक्रिया पर भी लिखित जवाब मांगा है। उनका मानना ​​है कि लॉन्च व्हीकल और सैटेलाइट निर्माण से इसरो के पीछे हटने से इन-हाउस काम घटेगा। उन्हें इस बात का डर है कि इससे मौजूदा कर्मचारियों को सरप्लस मान लिया जाएगा या उनके पास कोई काम नहीं बचेगा। इसके अलावा, युूप, ऋऔर ष पदों पर नियमित भर्तियां और भी कम हो जाएंगी, जिससे उन मेधावी युवाओं को निराशा होगी जो इसरो में काम करने का सपना देखते हैं।

रचनात्मक भावना से उठाई गई चिंता :हाल ही में मिशन की शानदार सफलता पर इसरो को बधाई देते हुए पत्र में कहा गया कि हमने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हम राख से उठकर फीनिक्स पक्षी की तरह उड़ सकते हैं। संघों ने स्पष्ट किया कि उन्होंने यह ज्ञापन एक रचनात्मक और लोकतांत्रिक भावना के साथ सौंपा है। उन्होंने कहा कि इसरो और राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रति हमारी वफादारी पर कोई सवाल नहीं है। इसी वफादारी के कारण हम मानते हैं कि अनिश्चितता के एक स्थायी नीति में बदलने से पहले स्पष्टता की मांग करना हमारा कर्तव्य है। संघों ने कहा है कि लिखित जवाब मिलने के बाद ही वे आगे की कार्रवाई तय करेंगे।

त्रिशूर में कार और बाइक की टक्कर में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत, ड्राइवर फरार



तिरुवनंतपुरम, एजेंसी। केरलम के त्रिशूर जिले में तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को इस घटना की जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, मृतकों की पहचान मुनीर (35), शिफना (24) और उनके तीन वर्षीय बेटे एमिल ऐबक के रूप में हुई है। ये सभी एडकझिप्पूर के निवासी थे। यह दर्दनाक हादसा शनिवार आधी रात के आसपास हुआ। जानकारी के अनुसार, जब यह दुर्घटना हुई, तब कार अत्यधिक तेज गति में थी और उसने परिवार की

मोटरसाइकिल को सीधे टक्कर मार दी। **नशे में था कार का ड्राइवर**: पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के वक्त कार का ड्राइवर कथित तौर पर नशे में था। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार और उसमें सवार दो अन्य यात्रियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि मुख्य आरोपी कार ड्राइवर अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। इस भीषण हादसे में कार और मोटरसाइकिल दोनों ही पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

केरलम में टिपर लॉरी और कार की टक्कर में दो लोगों की मौत: केरलम के त्रिशूर जिले में नेशनल हाईवे-

66 पर रविवार तड़के एक टिपर लॉरी और कार की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। मरने वाले लोग कूमाना के रहने वाले थे। कार में उनके साथ यात्रा कर रहे तीन घायलों को कोझिकोड मेडिकल कॉलेज के कैजुअल्टी वार्ड में ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि घायलों में से दो की हालत गंभीर है। ये पांचों दोस्त थे। पुलिस के अनुसार, यह हादसा सुबह करीब 3:30 बजे इपट्टिक्कल में कोझिकोड-त्रिशूर एनएच-66 (NH-66) पर हुआ। पुलिस ने बताया कि पथर ले जा रही एक टिपर लॉरी हाईवे पर आई और कुछ दूर चलने के बाद सर्विस रोड पर जाने के लिए यू-टर्न लिया, तभी वह विपरीत दिशा से आ रही कार से टकरा गई। स्थानीय लोगों ने कार को काटकर अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। पुलिस ने बताया कि हालांकि सभी पांचों यात्रियों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दो को मृत घोषित कर दिया गया। मृतकों के शव कोझिकोड मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में रखे गए हैं। थेनिपालम पुलिस मौके पर पहुंची, क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाया और ट्रैफिक बहाल किया। पुलिस ने घटना का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

11 दिन बाद भी तबाही का कहर: चीन-नेपाल आर्थिक गलियारा तबाह

मलबे से जिंदा निकलीं बुजुर्ग महिला और चीनी नागरिक

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल में आदि विनाशकारी बाढ़ और हिमस्खलन के 11 दिन बाद भी तबाही का मंजर जारी है। चीन-नेपाल के बीच जमीनी व्यापार का प्रमुख केंद्र ग्यिरोंग पोर्ट और उससे जुड़ी सीमा चौकी पूरी तरह तबाह हो चुकी है। लगातार सामने आ रहीं तस्वीरें इसकी भयावह स्थिति बयां कर रही हैं। चीन ने नेपाल में हुई इस तबाही से हुए नुकसान पर भले ही चुपची साध रखी हो, लेकिन इस आर्थिक गलियारे के ठप होने से नेपाल की अर्थव्यवस्था और आपूर्ति शृंखला पर असर साफ दिखने लगा है। भारत के जाने-माने भू-रणनीतिकार और अंतरराष्ट्रीय मामलों के विश्लेषक ब्रह्मा चेलानी का कहना है कि इस रास्ते होने वाला व्यापार पूरी तरह ठप होने से काठमांडो को अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए भारत पर और अधिक निर्भर होना पड़ेगा।

महंगाई का दिखने लगा असर : बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ट्रांस-हिमालय कनेक्टिविटी नेटवर्क में चीन ग्यिरोंग क्रॉसिंग को एक रणनीतिक केंद्र मानता है। ग्यिरोंग बंद होने से आपूर्ति शृंखला बाधित हो गई है। इससे चीनी सामानों की कमी हो रही है और नेपाल के घरेलू बाजार में महंगाई का दबाव बढ़ रहा है। यहां दोनों देशों के बीच ट्कों की आवाजाही, माल की चेकिंग, विलयरेंस और स्टोरेज के लिए बढ़े ड्राई पोर्ट और गोदाम बने थे।



लाखों टन मलबा साफ करने के बाद ही शुरू हो पाएगा मार्ग : तबाही के बाद व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह बहाल करने में अभी काफी समय लगेगा। भारी मालवाहक ट्रैफिक सुरक्षित रूप से फिर से शुरू होने से पहले इंजीनियरों को लाखों टन मलबा साफ करना होगा, ऊंचे पहाड़ी रास्तों को स्थिर करना होगा, हिमस्खलन के कारण ऊपर की ओर बनी झीलों के खतरे को कम करना होगा और बह चुके पुलों का पुनर्निर्माण करना होगा।

चमत्कार: दो और ज़िंदगियां बचाई गईं: अब इसे कुदरत का करिश्मा कहें या चमत्कार, नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के 11वें दिन शनिवार को मलबे में दबाए गए चार मंजिला महकन से एक बुजुर्ग महिला को जिंदा निकाला गया। परिजनों ने महिला के जीवित मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी और उनका प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार भी कर दिया था।

हैजा रोकने को मिला क्लोरीन: सूडान की सेना ने बना डाले 1,100 रासायनिक हथियार, गोपनीय डोजियर से खुलासा

खार्तूम, एजेंसी। तपते रेगिस्तान में चोरी-छिपे बम परीक्षण, हथियारों की सीक्रेट फैक्टरी के फर्श पर दम घुटने से मरे पड़े बिच्छू और कीड़े-मकोड़े, और जंग के बीच राजधानी खार्तूम के वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट से क्लोरीन के बड़े-बड़े सिलिंडरों की चोरी...गोपनीय डोजियर से सामने आई ऐसी कुछ जानकारीयां सूडान सरकार के इन दावों को नकारने के लिए काफी है कि उसने गृह युद्ध के दौरान रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया।

खुफिया रिपोर्ट में हुआ खुलासा: सूडान में पिछले तीन साल से जारी खूनी गृहयुद्ध के बीच एक पश्चिम एशियाई खुफिया एजेंसी की ओर से जुटाए गए 150 से अधिक दस्तावेजों, वीडियो, तस्वीरों और हजारों इंटरसेप्टेड फोन कॉल्स से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इससे पता चलता है कि सूडानी सेना ने अपने खिलाफ मोर्चा खोलने वाली रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) को पस्त करने के लिए 2024 में बड़े पैमाने पर क्लोरीन गैस आधारित रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया था। इस केमिकल प्रोजेक्ट की कमान ब्रिगेडियर जनरल तारिक हुसैन के हाथों में थी।

पारंपरिक वॉहेड के साथ क्लोरीन का उपयोग:



लीक ब्रूफ़िट के अनुसार, पारंपरिक वॉहेड के साथ 33 पाउंड क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया गया। योजना यह थी कि धमाके के छर्रों से दुश्मन घायल हो और बची-खुची जान जहरीली गैस ले लेगी। साथ ही धमाके के चलते मौके पर केमिकल के सबूत भी नष्ट हो जाएंगे।

राहत एजेंसियों की मदद का किया दुरुपयोग: राजधानी खारतूम पर जब आरएसएफ का कब्जा होने

लगा, तो जुलाई 2024 में जनरल तारिक ने सेना को क्लोरीन बम बनाने का सुझाव दिया। सेना ने ओमडुरमैन स्थित अल-मनारा वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट से बड़े पीले सिलिंडर जब्त किए। विडंबना यह है कि युद्धग्रस्त इलाकों में हैजा महामारी को रोकने और पानी साफ करने के लिए ये सिलिंडर यूनिसेफ, रेड क्रॉस और केयर जैसी अंतरराष्ट्रीय राहत एजेंसियों ने दान में दिए थे। अगस्त 2024 में जनरल हुसैन के भेजे गए संदेश से पता चलता है कि मिस्र से 20 क्लोरीन सिलिंडर मंगवाए गए थे, जो 1,100 रासायनिक बम बनाने के लिए पर्याप्त थे।

सेना प्रमुख ने दिए सबूत मिटाने के निर्देश: अमेरिकी प्रशासन ने कुछ सबूतों के आधार पर जनवरी 2025 से सूडानी सेना प्रमुख जनरल अब्देल फतह अल-बुरहान पर कड़े प्रतिबंध लगाने शुरू किए थे। अब सामने आए डोजियर से साफ हुआ है कि जनरल बुरहान को इस पूरे प्रोजेक्ट की सीधी जानकारी थी और उन्होंने अमेरिकी खुलासे के बाद इसके सभी सबूत मिटाने के निर्देश दिए थे।

दुश्मनों ने पी ली जहरीली गैस...सच कैसे सामने आया: अक्टूबर 2024 तक मेरोवे एयरपोर्ट के बेस पर

करीब 300 केमिकल बम तैयार करके रख दिए गए थे। 22 जुलाई 2024 को मेरोवे एयरपोर्ट से एंटोनेव विमान ने उड़ान भरी और रेगिस्तान में पहला सफल टेस्ट किया। लीक डोजियर से पता चलता है कि उसी समय जनरल हुसैन ने मैसेज भेजा था, परीक्षण 100% सफल रहा, बम निशाने पर गिरा और गैस फैल गई। सितंबर 2024 को अल-जैली तेल रिफाइनरी पर रासायनिक हमला किया गया। हुसैन के इंटरसेप्ट किए गए संदेश में लिखा था, उन्होंने गैस पी ली है। उस समय सोशल मीडिया पर विद्रोहियों को ऑक्सीजन मास्क पहने देखा गया था।

सबूत मिटाने का खेल: मई 2025 में जब अमेरिका ने रासायनिक हथियारों के संदेह पर सूडान पर प्रतिबंध लगाए, तो सेना प्रमुख जनरल बुरहान ने तुरंत जनरल हुसैन को मैसेज भेजकर सबूत मिटाने का फरमान सुनाया।

जवाब मिला. ऑपरेशन एक महीने पहले ही पूरा कर दिया गया है। बाद में दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए बुरहान ने आरोपों की जांच के लिए एक आंतरिक कमेटी गठित की। इसका मुख्य सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल तारिक हुसैन को ही बना दिया गया।

अमेरिकी सेना बच्चों की हत्यारी, उनका झूठा गौरव तोड़ा, हमले के बाद ईरान ने यूएस को लताड़ा, दे डाली धमकी

वाशिंगटन, एजेंसी। भारत में स्थित ईरान के दूतावास ने छह सितंबर, 2026 को एक्स अकाउंट पर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी का बयान साझा किया। बयान के मुताबिक, आईआरजीसी की एग्रोस्पेस फोर्स ने अमेरिकी सेना के एक विमानवाहक पोत और एक विध्वंसक पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। ईरान ने आरोप लगाया कि दोनों अमेरिकी युद्धपोत ईरानी जहाजों को परेशान कर रहे थे और ईरान की नौसैनिक नाकाबंदी में हिस्सा ले रहे थे।

ईरान ने अमेरिकी सेना को बच्चों की हत्या करने वाली क्यों बताया: आईआरजीसी ने अपने बयान में अमेरिकी सेना को खूब सुनाया। उसने अमेरिकी सेना को आक्रामक और बच्चों की हत्या करने वाली अमेरिकी सेना बताया। ईरानी संगठन ने दावा किया कि मिसाइल हमले के बाद दोनों अमेरिकी युद्धपोतों को नुकसान पहुंचा और आगे के हमले के डर से उन्हें मुठभेड़ वाले इलाके से भागना पड़ा। **अमेरिका के झूठे गौरव को लेकर ईरान ने क्या कहा**: ईरान ने अमेरिका को आक्रामक दुश्मन बताते हुए कहा कि वह कई वर्षों से क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को लेकर घमंड करता रहा है। आईआरजीसी के मुताबिक, अमेरिकी पक्ष को अब आधिकारिक रूप से यह स्वीकार करना पड़ा कि उसके दो नौसेना युद्धपोत हमले की चपेट में आए। ईरानी संगठन ने इस घटनाक्रम को अमेरिकी रणनीतिक हार बताया और कहा कि इससे आईआरजीसी की हमला करने की क्षमता सामने आती है।

आईआरजीसी ने अपनी सैन्य ताकत को



लेकर क्या कहा: आईआरजीसी ने कहा कि वह और ईरान की दूसरी सशस्त्र सेनाएं देश की संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा के लिए पूरी तरह दृढ़ हैं। संगठन ने दावा किया कि ईरानी जनता की मौजूदगी और उसके लड़ाकों का लगातार प्रतिरोध अमेरिका को अपने कथित उद्देश्यों में सफल नहीं होने देगा। यानी ईरान ने अपने बयान के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की कि अमेरिकी दबाव के बावजूद वह पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है।

अमेरिका को ईरान ने क्या सीधी धमकी दी3 आईआरजीसी ने साफ चेतावनी दी कि अगर अमेरिका की 'शत्रुतापूर्ण और आक्रामक कार्रवाई' जारी रहती है तो उसे ईरानी सशस्त्र बलों की 'विनाशकारी प्रतिक्रिया' का सामना करना पड़ेगा। बयान में ईरान ने खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बताया और कहा कि जीत उसके दृढ़ लोगों की होगी, जबकि हमलावरों के लिए हार और पछतावा तय है।

ऑपरेशन के बाद मरीजों को दी जाएगी होम्योपैथी की दवा

कोलकाता के एनआईएच में शुरू होगा नई चिकित्सा पद्धति पर शोध



है। इन पहलुओं का क्लिनिकल रिसर्च के माध्यम से मूल्यांकन किया जाएगा। संस्थान के नियमित मरीज को आपरेशन

की जरूरत पड़ने पर बाहर रेफर करने के बजाय एनआईएच में ही उसके उपचार की पूरी व्यवस्था करने की योजना है। ऑपरेशन के दौरान एनेस्थेटीस्ट, सर्जन और जरूरत के अनुसार कार्डिथोलॉजिस्ट की भूमिका एलोपैथी चिकित्सक निभाएंगे। वहीं, ऑपरेशन के बाद इस्तेमाल होने वाली दवाओं में होम्योपैथी को शामिल किया जाएगा।

छात्रों को सर्जरी की सीमा और जरूरत समझाने पर जोर

प्रलय शर्मा ने बताया कि एनआईएच में बैचलर आफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएसएमएस) पाठ्यक्रम संचालित होता है। पाठ्यक्रम के नाम में ही सर्जरी शामिल है। नए मॉड्यूलर आपरेशन थिएटर के जरिए छात्रों को यह समझने का अवसर मिलेगा कि किन बीमारियों में ऑपरेशन जरूरी होता है और किन स्थितियों में दवाओं से उपचार संभव है। संस्थान के अनुसार, आपरेशन के बाद होम्योपैथी दवाओं से अतिरिक्त लाभ मिलता है या नहीं, इसे वैज्ञानिक रूप से परखने का अवसर मिलेगा। एनआईएच का कहना है कि एलोपैथी दवाओं की तुलना में होम्योपैथी दवाओं में सक्रिय औषधीय घटकों की मात्रा कम होती है, क्योंकि होम्योपैथी में मूल पदार्थ को बार-बार घोलकर पतला किया जाता है। इसी अंतर को ध्यान में रखते हुए पोस्ट-ऑपरेटिव उपचार में इनके प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा।

‘हनुमान अंश’ ने रचा इतिहास, एक दिन में बजट से 11 गुना ज्यादा कमाई कर ली



बॉक्स ऑफिस पर कब कौन सी फिल्म अचानक बड़ा कारनामा कर दे, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता. और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई ‘हनुमान अंश’. शायद मेकर्स ने भी नहीं सोचा होगा कि महज 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी ये फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी. रिलीज के एक महीने के बाद भी फिल्म का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. रिलीज के 31वें दिन तो इस पिक्चर ने इतिहास ही रच दिया है.सैकनलिक के मुताबिक 31वें दिन (रविवार) ‘हनुमान अंश’ ने 22.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. यानी बजट से 11 गुना से भी ज्यादा. और ये इस पिक्चर का एक दिन का सबसे हाईएस्ट कलेक्शन है. इससे पहले किसी भी दिन इस फिल्म ने इतनी ज्यादा कमाई नहीं की थी. इससे पहले सिंगल डे पर फिल्म का हाईएस्ट कलेक्शन 16.50 करोड़ रुपये था, जो 30वें दिन फिल्म ने अपने नाम किए थे.‘हनुमान अंश’ ने महज 10 लाख रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग की थी. 16वें दिन तक ये फिल्म लाखों में ही कमाई कर रही थी. किसी भी दिन फिल्म का कलेक्शन एक करोड़ को टच नहीं किया था. हालांकि, 17वें दिन 2.20 करोड़ रुपये कमाए, उसके बाद से फिल्म की रफ्तार जारी है. अगर बात टोटल कलेक्शन की करें तो 31 दिनों में फिल्म ने 122.13 करोड़ रुपये अपने नाम कर लिए हैं.कमाई के ये आंकड़े सिर्फ घरेलू बॉक्स ऑफिस के हैं. भारत में धूम मचाने के बाद अब मेकर्स ने इस पिक्चर को विदेशों में भी रिलीज करने का फैसला किया है. 11 सितंबर को ‘हनुमान अंश’ भारत के बाहर रिलीज की जाएगी. ओवरसीज में इस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन होम्बले फिल्म्स कर रही है. इसी कंपनी ने चतख, पुष्पा, कांतारा और सालार जैसी फिल्मों का निर्माण किया है. अब ये कंपनी विदेशों में ‘हनुमान अंश’ को डिस्ट्रीब्यूट करेगी.



मिर्जापुर द मूवी ने मचाया तहलका, आवारापन 2 को पछाड़ बनी चौथी बड़ी ओपनर

ओटीटी पर अपनी अलग पहचान बनाने वाली मिर्जापुर की कहानी अब सिनेमाघरों तक पहुंच चुकी है। मिर्जापुर द मूवी को लेकर दर्शकों में पहले से ही जबरदस्त उत्सुकता थी, लेकिन फिल्म देखने के बाद साफ है कि बड़े पर्दे के लिए कहानी को सिर्फ दोहराया नहीं गया है। मेकर्स ने पुराने किरदारों और पहचान वाले माहौल को बरकरार रखते हुए कहानी में नए मोड़ जोड़े हैं। खास बात यह है कि ओटीटी वाली बर्बरता और खून-खराबे को सिनेमाई दर्शकों के हिसाब से थोड़ा संतुलित किया गया है, लेकिन मिर्जापुर का दबदबा और सत्ता की लड़ाई अब भी पूरी तरह कायम है।फिल्म की कहानी एक बार फिर मिर्जापुर की सत्ता के इर्द-गिर्द घूमती है। कालीन भैया यानी पंकज त्रिपाठी, गुड्डू पंडित यानी अली फजूल, बबलू पंडित के किरदार और मुन्ना भैया से जुड़े पुराने हिसाब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इस बार मामला सिर्फ गद्दी हासिल करने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे मिर्जापुर पर अपना वर्चस्व कायम करने की जंग नजर आती है। पुराने रिश्तों, दुश्मनी और बदले के बीच हर किरदार अपने तरीके से चाल चलता दिखाई देता है। मिर्जापुर द मूवी में नए किरदारों की एंट्री कहानी को एक अलग दिशा देती है। जैसलमेर से जुड़े झग माफिया के खतरनाक खिलाड़ी बब्बन यादव के रूप में रवि किशन की मौजूदगी फिल्म में नया तनाव पैदा करती है। उनका किरदार मिर्जापुर की पहले से उलझी सत्ता की लड़ाई को और पेचीदा बना देता है। दूसरी तरफ बीना त्रिपाठी के रूप में रसिका दुग्गल और शरद शुक्ला के किरदार में अंजुम शर्मा भी अपने-अपने तरीके से कहानी में दांव-पेच जोड़ते हैं।मिर्जापुरकी पिछली कहानी में मुन्ना भैया का अंत दिखाया जा चुका था, लेकिन फिल्म में दिव्येंद्रु की वापसी ने दर्शकों को खास सरप्राइज दिया है। उनका अंदाज और चर्चित स्वेग फिर से देखने को मिलता है। हालांकि ओटीटी सीरीज जैसी चौंकाने वाली शॉक वैल्यू यहां कम महसूस हो सकती है, लेकिन नए ट्रैक, नए किरदार और तेज घटनाक्रम फिल्म को लगातार आगे बढ़ाते हैं।रिलीज के पहले ही दिन मिर्जापुर द मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बनाई।



हार्दिक पांड्या से जोड़ा नाम, अमीषा पटेल यूजर को दिया करारा जवाब

एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने एक सोशल मीडिया यूजर को करारा जवाब दिया है, जिसने उन्हें क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के साथ रोमांटिक रूप से जोड़ने की कोशिश की थी।एक्ट्रेस ने एक वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया दी जिसमें दोनों साथ दिख रहे थे और साफ़ किया कि दोस्ती भरें व्यवहार को कुछ और नहीं समझना चाहिए। हार्दिक और अमीषा को हाल ही में मुंबई के ताज महल पैलेस में एक साथ देखा गया था। इस मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें अमीषा क्रिकेटर को अपने कुछ दोस्तों से मिलवा रही थीं। यह वीडियो तब चर्चा में आया जब एक झू यूजर ने इसे शेयर किया और कहा कि उनके बीच कुछ और भी हो सकता है। वीडियो शेयर करते हुए झू यूजर ने लिखा, बेंगलुरु के एक होटल में पार्टी के दौरान अमीषा पटेल ने जिस तरह हार्दिक पांड्या के कंधे पर हाथ रखा... ऐसा लगता है कि रेडिट की सारी अफवाहें सच हो रही हैं।बाद में अमीषा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर उस पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया और डेंटिंग की अटकलों पर तंज कसते हुए जवाब दिया। यूजर को सोच पर मज़ाक उड़ाते हुए उन्होंने लिखा, बिल्कुल सही कहा। हे भगवान, तुम सही हो... सच में, जिस तरह से मेरा हाथ उन पर था, वह कितना रोमांटिक था।इसके बाद एक्ट्रेस ने यूजर पर एक और तंज कसा और सवाल किया कि दोस्तों के बीच हुई आम बातचीत में वह रोमांटिक एंगल क्यों ढूंढ रहे हैं।



हंसल मेहता की बाराबंकी फिल्म से करेंगी कमबैक

6 साल बाद वापसी करने जा रही बिपाशा

फिल्मों में तो उन्होंने काम करना

काफ़ी पहले ही छोड़ दिया था.

शादी के बाद से एक्ट्रेस ने फिल्मों

में काम नहीं किया और ओटीटी

पर भी वे 2020 में एक वेब

सीरीज में नजर आई थीं.

कोरोना फेज के दौरान ही उन्होंने अभिनय की दुनिया से दूरी बना ली थी और उनकी पब्लिक अपीयरेंस भी कम हो गई थी.

अब एक्ट्रेस एक बार फिर से वापसी के लिए तैयार हैं.

बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में पोस्ट कोरोना फेज में कई सारे कलाकार ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने करियर में वापसी की है. इनमें कई सारी एक्ट्रेस भी शामिल हैं जिन्होंने काफी पहले ही फिल्मों से दूरी बना ली थी. इसी में एक नाम अब बिपाशा बसु का भी जुड़ गया है. बिपाशा ने 6 साल के ब्रेक के बाद अब वापसी करने का फैसला लिया है. एक्ट्रेस अब एक वेब सीरीज में नजर आएंगी.

फिल्मों में तो उन्होंने काम करना काफी पहले ही छोड़ दिया था. शादी के बाद से एक्ट्रेस ने फिल्मों में काम नहीं किया और ओटीटी पर भी वे 2020 में एक वेब सीरीज में नजर आई थीं. कोरोना फेज के दौरान ही उन्होंने अभिनय की दुनिया से दूरी बना ली थी और उनकी पब्लिक अपीयरेंस भी कम हो गई थी. अब एक्ट्रेस एक बार फिर से वापसी के लिए तैयार हैं.

किस प्रोजेक्ट से वापसी कर रही बिपाशा बसु?

बिपाशा बसु की बात करें तो वे दिग्गज डायरेक्टर हंसल मेहता की अपकमिंग सीरीज बाराबंकी में नजर आने वाली हैं. इसमें बिपाशा के अलावा विशाल जेटवा और सनी कौशल भी नजर आएंगे. इसमें उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में ड्रग्स की तस्करी की कहानी दिखाई जाएगी. अभी इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट नहीं हुई है लेकिन रिपोर्ट्स की मानें तो बिपाशा ने इसकी शूटिंग शुरू कर दी है. पिछले महीने ही इस सीरीज की शूटिंग शुरू कर दी गई है जो मुंबई में हो रही है.

एक्ट्रेस के पिछले कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वे डेंजरस नाम की एक सीरीज में नजर आई थीं. इस सीरीज से उन्होंने अपना ओटीटी डेब्यू किया था. वहीं फिल्मों की बात करें तो लीड एक्ट्रेस के रोल में उनकी पिछली अपीयरेंस अलोन थी जिसमें वे डबल रोल प्ले करती नजर आई थीं. अब उनकी इस अपकमिंग सीरीज को लेकर बज बनना शुरू हो चुका है. इसकी कहानी आलोक लाल की किताब द बाराबंकी नाकॉज बस्टिंग इंडिया मोस्ट नोटोरियस ड्रग कार्टेल से प्रेरित है. देखने वाली बात होगी कि लंबे ब्रेक के बाद बिपाशा किस तरह से वापसी करती हैं और मेकर्स के भरोसे पर कितना खड़ा उतरती हैं.



लड़ाई-झगड़े, किचन की सियासत, राशन पर महाभारत और सभी पर 100 कैमरों की पैनी नजरजटेलीविजन का सबसे बड़ा और विवादित रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ आखिरकार शुरू हो चुका है. होस्ट सलमान खान ने अपने उसी स्वेग के साथ ग्रैंड प्रीमियर की रात घर का मुख्य दरवाजा खोल दिया है. 20वें सीजन को खास बनाने के लिए मेकर्स ने इस बार टीवी, बॉलीवुड, खेल, भोजपुरी सिनेमा और सोशल मीडिया का ऐसा कॉकटेल तैयार किया है, जो पहले दिन से ही चिंगारी भड़काने के लिए तैयार है.

कनिका मान

‘गुड्डुन तुमसे ना हो पाएगा’ की सीधी-सादी बहू और ‘खतरों के खिलाड़ी’ में स्टैंट्स से होश उड़ाने वाली कनिका मान शो की ग्लैमरस और मजबूत कंटेस्टेंट हैं, जिनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. टीवी की इस मशहूर एक्ट्रेस ने सबसे पहले शो में एंट्री की.

आसिफ खान

‘पंचायत’ के ‘दामाद जी’ (गजब बेइज्जती है) और ‘मिर्जापुर’ में बाबर का रोल निभाकर घर-घर में मशहूर हुए एक्टर आसिफ खान भी इस बार घर में बंद हुए हैं. ओटीटी का यह संजीदा एक्टर बिग बॉस के अखाड़े में क्या रंग दिखाता है, यह देखना मजेदार होगा.

काजी तौकीर

साल 2005 के कल्ट शो ‘फेम गुरुकुल’ के विनर और सिंगर काजी तौकीर सालों बाद स्क्रीन पर लौटे हैं. उनका वहीं अनूठा स्टाइल और 90हज़ा-2000हज़ा का नोस्टैल्जिया दर्शकों को खूब पसंद आने वाला है.

इंशा रिखी

पंजाबी फिल्मों की जानी-मानी एक्ट्रेस और मॉडल इंशा रिखी अपनी खूबसूरती और पर्सनैलिटी से प्रीमियर पर ही छाई रहीं. उनके ग्लैमरस अंदाज पर अभी से सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो चुकी है.

मेरी कॉम

इस सीजन का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला नाम हैं छह बार की वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक मेडलिस्ट बॉक्सर मेरी कॉम. रिंग में बड़े-बड़े मुक़्केबाजों को धूल चटाने वाली मेरी कॉम का बिग बॉस के घर में आना अपने आप में ऐतिहासिक है. देखना दिलचस्प होगा कि उनका अनुशासन घर के ड्रामे को कैसे झेलता है.

आम्रपाली दुबे

भोजपुरी सिनेमा की ‘क्रोन’ आम्रपाली दुबे की मौजूदगी शो में ठेठ यूपी-बिहार का देसी तड़का लगाने वाली है. उन्हें शो तक छोड़ने के लिए भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ खुद आए थे. रोजनल सिनेमा का बड़ा चेहरा होने के नाते उनके पास वोटों की कोई कमी नहीं रहने वाली.

अरिशफा खान

चाइल्ड आर्टिस्ट से सोशल मीडिया सेंसेशन बनी अरिशफा खान के इंस्टाग्राम पर करीब 30 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. जेनरेशन-जी (बढ़ड़ू-) का यह चेहरा घर के समीकरण बदलने का पूरा दम रखता है.

यंग डी.एस.ए

पुणे के यरवदा की गलियों से निकलकर हिप-हॉप की दुनिया में तहलका मचाने वाले राइजिंग रैपर यंग डी.एस.ए (असली नाम- हर्ष विजय मचारे) की एंट्री ने शो में अंडरग्राउंड स्ट्रीट-स्वैग का तड़का लगा दिया है. ‘येड़ा यंग’ और ‘फचाड़ी’ जैसे गानों से इंटरनेट पर वायरल सनसनी बनने वाले इस रैपर का अंदाज एकदम बेबाक और रॉ है. पुणे के यरवदा से निकलकर सीधे सलमान खान के शो तक का सफर तय करने वाले यंग डी.एस.ए का यह अनफिल्टर्ड मिजाज घर के सो-कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड कंटेस्टेंट्स के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है.

तन्मय सिंह उर्फ स्काउट

भारत के सबसे बड़े ई-गेम्स और यूट्यूबर्स में गिने जाने वाले स्काउट की एंट्री यूथ ऑडियंस को सीधे शो से जोड़ेगी. गेमिंग की दुनिया में सटीक रणनीति बनाने वाले स्काउट बिग बॉस के चक्रव्यूह को कैसे भेदते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा.

रोहेद खान

फैशन और मॉडलिंग की दुनिया का जाना-पहचाना

नाम रोहेद खान इस सीजन में बतौर मॉडल और यूथ कंटेस्टेंट अपनी किस्मत आजमाने उतरे हैं.

उदित सिंह

मॉडल और सोशल मीडिया पर्सनैलिटी उदित सिंह की एंट्री से भी घर का तापमान बढ़ने वाला है. उनका बेबाक और ग्लैमरस अंदाज पहले ही दिन नजर आ गया.

अमन गांधी

टेलीविजन के जाने-माने एक्टर अमन गांधी अपने चार्मिंग अंदाज और टीवी बैकग्राउंड के सहारे खेल को आगे ले जाने की तैयारी में हैं.

कुशल तंवर उर्फ गुलू

‘एमटीवी रोडीज़’ के विजेता और रियलिटी शोज़ के मझे हुए खिलाड़ी गुलू का टास्क और माईडोम में कोई सानी नहीं है. उनका अग्रेसिव अंदाज घर में पहले हफ्ते से ही पंगा करवा सकता है.

लव गिल

पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की जानी-मानी मॉडल और एक्ट्रेस लव गिल अपनी चुलबुली और बिंदास पर्सनैलिटी के साथ घर का माहौल गरमाने पहुंची हैं.

रीति तिवारी

भोजपुरी सुपरस्टार और सांसद मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी बतौर सिंगर-कंपोजर इस बार घर में अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने उतरी हैं.

माही विज

‘बालिका वधू’ और ‘लागी तुझसे लगन’ फेम माही विज लंबे समय से टीवी की चहेती रही हैं. हालिया पर्सनल लाइफ की उथल-पुथल और टीवी इंडस्ट्री के तजुबों के साथ माही टॉफी के लिए इस सीजन की सबसे मजबूत दावेदारों में से एक मानी जा रही हैं।

हाफ्टाइम तक भारत 2-1 से आगे था। तीसरे क्वार्टर में भी यही सिलसिला जारी रहा। दोनों टीमों में नियंत्रण हासिल करने के लिए संघर्ष करती रहीं।

सार समाचार

45 हजार बिजली कर्मचारी करेंगे काम बंद

भोपाल । प्रदेश में बिजली आउटसोर्स व्यवस्था खत्म कर पंजाब की तर्ज पर नई आउटसोर्स सुधार सविदा नीति लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर बिजली आउटसोर्स कर्मचारी आंदोलन की तैयारी में है। मध्यप्रदेश के सभी 55 जिलों के करीब 45 हजार बिजली आउटसोर्स ठेका कर्मचारी 7 और 8 नवंबर 2026 को काम बंद आंदोलन करेंगे। इसका ऐलान मप्र बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रांतीय संयोजक मनोज भागव ने किया है।भागव ने कहा कि भाजपा ने 2023 के विधानसभा चुनाव के वचन-पत्र में आउटसोर्स कर्मचारियों को सविदा कर्मचारी बनाने का वादा किया था, लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं हुआ। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें केंद्र के आउटसोर्स कर्मियों के समान न्यूनतम वेतन दिया जाए। उन्होंने कहा कि पंजाब में बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों को सविदा कर्मचारी बनाने के लिए विधानसभा से विधेयक पारित हो चुका है, जबकि मप्र में इस दिशा में पहल नहीं हुई है।एद समाप्त करने और बोनस नुकसान का आरोपवहीं, बिजली कंपनियों के नए संगठनात्मक ढांचे में करीब 23 हजार पद खत्म किए गए हैं, जिससे कर्मचारियों को भविष्य में छंटनी और बेरोजगारी का डर है। संगठन का आरोप है कि बोनस की दर बढ़ाने के आदेश के बावजूद 69 महीने से पुरानी दर से भुगतान हो रहा है। इससे प्रत्येक कर्मचारी को करीब 80 से 90 हजार रुपये का नुकसान हुआ है। कर्मचारियों ने मांगें पूरी नहीं होने पर धर्तरेस की रात से दीपावली की मध्यरात्रि तक सामूहिक अवकाश लेने की चेतावनी दी है।

17 सितंबर को भोपाल सहित प्रदेशभर की मंडियों में रहेगी हड़ताल

भोपाल । पिछले दिनों कृषि उपज मंडी टैक्स में की गई बढ़ोतरी सहित अन्य मांगों को लेकर व्यापारियों ने विरोध किया था। मगर शासन ने टैक्स में कमी नहीं की। सकल अनाज दलहन-तिलहन महासंघ का जो प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन हुआ, उसमें यह निर्णय लिया गया कि 17 सितम्बर को भोपाल सहित प्रदेशभर की मंडियां बंद रहेगी और व्यापारी भोपाल पहुंचकर कृषि मंत्री से मुलाकात करेंगे। मंडी नियमों में प्रस्तावित संशोधन, नामांतरण, नामाकरण शुल्क में वृद्धि, पैनल्टी सहित ऑनलाइन पोर्टल की जटील प्रक्रिया सहित जो मांगें रखी गई थी उन पर शासन स्तर पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। व्यापारी महासम्मेलन में प्रदेशभर के व्यापारी, मंडी प्रतिनिधि व अन्य अनाज दलहन-तिलहन कारोबार से जुड़े व्यापारी शामिल हुए और इस महासम्मेलन में मंडी से जुड़ी समस्याओं-व्यवस्थाओं, नियमों पर अपनी बात कही और अतिरिक्त टैक्स वृद्धि वापस लेने और भविष्य में कोई भी नियम बनाने से पहले व्यापारियों से पर्याप्त सहमति और चर्चा करने की बात भी कही। अध्यक्ष के मुताबिक 17 सितम्बर को देशभर में मंडियों को बंद रखा जाएगा।

31 अक्टूबर तक चुका सकेगेवन टाइम सेटलमेंट में बकाया लीज रेंट

भोपाल । हाउसिंग बोर्ड अपने हजारों लीज रेंट बकायादारों को अब 31 अक्टूबर तक वन टाइम सेटलमेंट योजना का लाभ देगा। पूर्व में 31 मार्च तक ही इसकी समय सीमा तय कर रखी थी, जिसके चलते कई अन्य बकायादारों ने अध्यक्ष से समय बढ़ाने का अनुरोध किया, जिसके चलते अभी आयुक्त ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। दरअसल, भोपाल सहित प्रदेशभर में हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष ओम जैन ने पिछले दिनों लगातार समाधान शिबिर लगाए, जिसमें बोर्ड से जुड़ी समस्याओं के साथ-साथ इस योजना की अवधि बढ़ाने की मांग भी कई आवेदकों ने की, जिसके चलते अब समय सीमा बढ़ाने का आदेश जारी किया गया।दरअसल, कई आबंटितों द्वारा लीज रेंट ना चुकाने पर भारी-भरकम पैनल्टी भी लगाई गई है और पहले 31 मार्च तक इसमें छूट दी गई थी, अब उसी तरह की छूट मिलेगी, जिसमें पैनल्टी माफ की जाएगी, लेकिन किरतों को बजाय बकाया लीज रेंट एकमुश्त यानी एक साथ ही चुकाना पड़ेगा। इसके बाद फ्री होल्ड सहित अन्य लाभ भी आबंटितों से सकेगा। अभी हाउसिंग बोर्ड द्वारा फ्री होल्ड योजना का लाभ भी दिया जा रहा है। मगर इसमें एक समस्या यह भी आ रही है कि कई स्थानों पर हाउसिंग बोर्ड के जो प्रोजेक्ट अमल में लाए गए उनकी जमीनों का नामांतरण बोर्ड के नाम पर रास्टर रिर्कोर्ड में नहीं हुआ, जिसके चलते ये जमीन अभी भी सरकारी या अन्य वदी में दर्ज है। नतीजतन इन प्रोजेक्टों के आबंटितों को फ्री होल्ड का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हाउसिंग बोर्ड इसके लिए नजूल निवर्तन अधिनियम के तहत आबंटितों से कहता है कि वह प्रशासन के पास जानकर फ्री होल्ड की प्रक्रिया करवाए। हालांकि इस बारे में हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष जैन ने पहल की है और उन्होंने राज्यस् मंत्री के साथ-साथ कलेक्टरों से चर्चा की है, ताकि रास्टर रिर्कोर्ड में हाउसिंग बोर्ड के नाम जमीन दर्ज हो जाए, जिससे बोर्ड खुद फ्री होल्ड की प्रक्रिया आसानी से कर सकेगा।

भारी बारिश से बड़े बांध 70 प्रतिशत से ज्यादा भरे

भोपाल । मध्य प्रदेश में मानसून की शुरूआती बेरुखी के बाद अब अखी संकेत मिलने लगे हैं। भारी बारिश के दौर से प्रदेश में कोटे की 82.3 प्रतिशत बारिश हो चुकी है, जिससे बड़े बांध 70 फीसदी से ज्यादा भर चुके हैं। भोपाल समेत 12 जिलों की बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। हालांकि, कुछ जिले ऐसे भी हैं, जहां औसत से काफी कम बारिश हुई है। प्रदेश के मऊरंग, सतना, निवाड़ी जिले में प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, तो वहीं अलीराजपुर में इस बार औसत से 54 फीसदी कम बारिश हुई है।मौसम विभाग के भोपाल केंद्र के अनुसार, राजधानी भोपाल के साथ-साथ राजगढ़, शिवपुरी, निवाड़ी, मेहर, भिंड, श्योपुर, सिंगरीली, सीधी, सतना, मऊरंग और शहडोल का बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। इन क्षेत्रों में 101 से 146 प्रतिशत तक पानी गिर चुका है। प्रदेश के करीबन एक दर्जन जिलों में अभी भी जोरदार बारिश का ईर्जजार हो रहा है। इससे ज्यादा इंतजार अलीराजपुर जिले में ही है। यहां औसत बारिश का आधा कोटा भी पूरा नहीं हुआ है। अलीराजपुर में सिर्फ 345 मिलीमीटर बारिश हो हुई है यानी औसत से 54 फीसदी कम। धार जिले में औसत से 41 फीसदी कम बारिश हुई है। धार में औसतन 695 मिलीमीटर बारिश होती है।

मप्र के नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाइयों में ही होगी दिल की जांच

अब मासूमों जन्मजात बीमारी जल्दी पकड़ने की तैयारी



भोपाल । मध्य प्रदेश में जन्मजात हृदय रोग से जूझ रहे नवजात बच्चों की बीमारी पकड़ ? में होने वाली देरी कम करने की तैयारी है। अब गंभीर हालत में भर्ती शिशुओं को केवल हृदय की जांच के लिए दूसरे अस्पताल या मेडिकल कॉलेज भेजने की जरूरत कम होगी। स्वास्थ्य विभाग प्रदेश के सभी नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाइयों

मशीनों लगाने की दिशा में काम कर रहा है। फिलहाल छह मशीनें खरीदी गई हैं। इन्हें छह जिला अस्पतालों के एसएनसीयू में स्थापित किया जाएगा। खरगोन, बड़वानी और विदिशा में मशीन लगाने का निर्णय हो चुका है, जबकि अन्य तीन अस्पतालों का चयन जल्द किया जाएगा। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के बाकी एसएनसीयू को भी ईको मशीनों से लैस

किया जाएगा।जन्मजात हृदय रोग की पहचान में सबसे बड़ी चुनौती गंभीर हालत में भर्ती नवजात को जांच के लिए दूसरी जगह ले जाना है। यदि एसएनसीयू में भर्ती बच्चे में दिल की बीमारी के संकेत मिलते हैं तो सामान्य स्थिति में उसे ईकोकार्डियोग्राफी के लिए मेडिकल कॉलेज भेजना पड़ सकता है। लेकिन कई बार नवजात को हालत ऐसी होती है कि उसे दूसरी

जगह ले जाना जॉखिम भरा हो सकता है। ऐसे में जांच में देरी हो सकती है और बीमारी की पहचान भी देर से होती है। नई व्यवस्था में जांच की सुविधा उसी एसएनसीयू में उपलब्ध कराने पर जोर है। इसका सीधा फायदा उन बच्चों को मिलेगा जिन्हें जन्म के तुरंत बाद विशेष निगरानी और उपचार की जरूरत होती है।

छह अस्पतालों से शुरुआत, लक्ष्य पूरे प्रदेश का

पहले चरण में छह जिला अस्पतालों के एसएनसीयू में ईको मशीनें लगाई जा रही हैं। इसके बाद दूसरे चरण में अन्य इकाइयों को शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रदेश के जिला स्तर के नवजात देखभाल केंद्रों को इतना सक्षम बनाना है कि गंभीर नवजात में हृदय संबंधी समस्या की प्राथमिक पहचान के लिए हर बार मेडिकल कॉलेज पर निर्भर न रहना पड़े। यदि यह व्यवस्था सभी एसएनसीयू में प्रभावी तरीके से लागू होती है

एआईएम कांग्रेस-2026 में शामिल हुए सीएम डॉ. मोहन यादव, निवेशकों को दिया मध्यप्रदेश आने का निमंत्रण

युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के रास्ते

भोपाल । मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 7 सितंबर को दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित ह्यूएआईएम कांग्रेस-2026हू (एनुअल इवेस्टमेंट मीटिंग) में पहुंचे। उनका यह दुबई प्रवास मध्यप्रदेश में निवेश और रोजगार के रास्ते खोलेगा। यह सम्मेलन राज्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इस सम्मेलन में डॉ. यादव ने निवेशकों को भोपाल में आयोजित होने वाली ग्लोबल इवेस्टर मीट -2027 के लिए आमंत्रित किया। एआईएम कांग्रेस दुनिया के सबसे बड़े निवेश मंचों में से एक है। इस सम्मेलन में 180 से ज्यादा देशों के करीब 20,000 प्रतिनिधि हो रहे शामिल। यहां सरकारें, बड़े निवेशक, सोवरिन वेल्थ फंड्स और कंपनियां एक मंच पर आकर निवेश के मौकों पर चर्चा करती हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यहां बड़े निवेशकों और कंपनियों से सीधे मुलाकात की। एक ही जगह पर दुनिया भर के निवेशक मौजूद हैं। इसलिए यह मध्यप्रदेश के लिए बड़ा और किफायती

अवसर है। उन्होंने पहले दिन यहां ताज दुबई के बिजनेस बे में आयोजित मध्यप्रदेश के ओडीओपी (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट) एवं भौगोलिक संकेतक (जीआई) उत्पादों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रदर्शनी का उद्घाटन कर मध्यप्रदेश की समृद्ध हस्तशिल्प, हथकरघा और पारंपरिक कला विरासत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित किया। इस प्रदर्शनी में बैतुल का बेल मेटल क्राफ्ट, अशोकनगर की चंदेरी साड़ी, खरगोन के महेश्वर की महेश्वरी साड़ी, उज्जैन का बाटिक प्रिंट, भोपाल की जरी-जरदोजी तथा ग्वालियर कार्पेट शामिल हैं। ये उत्पाद मध्यप्रदेश के पारंपरिक कौशल, सांस्कृतिक विविधता और निर्यात क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य इन उत्पादों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाना, अंतर्राष्ट्रीय खरीददारों से जोड़ना और कारीगरों के लिए नए आर्थिक अवसर सृजित करना है।

अरब संसद के अध्यक्ष से की अहम मुलाकात

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अरब संसद के अध्यक्ष मोहम्मद अहमद अल यामाही से मुलाकात की। उन्होंने अरब देशों और मध्यप्रदेश के बीच व्यापार, निवेश, कृषि, पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्रों में व्यापक सहयोग की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने अरब निवेशकों को मध्यप्रदेश के नवकरणीय ऊर्जा, औषधि निर्माण, चिकित्सा उपकरण, वस्त्र, लॉजिस्टिक्स, उन्नत विनिर्माण और शहरी अवसंरचना क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मोहम्मद अहमद अल यामाही तथा उनके नेतृत्व वाले अरब व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल को मध्यप्रदेश का दौरा करने और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 में सहभागी बनने का आमंत्रण दिया।

किसानों के लिए प्रतिबद्ध सीएम डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की यात्रा निवेश पर केंद्रित है। उनके नेतृत्व में मध्यप्रदेश एक ग्लोबल निवेश के रूप में सामने आएगा। इससे जीआईएस-2027 की तैयारी को भी मजबूती मिलेगी। दुबई अपनी जरूरत का 85प्रति. से ज्यादा खाना बाहर से मंगाता है। साल 2024 में यूपई ने करीब 16.2 बिलियन डॉलर का खाद्य आयात किया, जो 2023 से 13.7प्रति. ज्यादा है। वहां की लगभग 89प्रति. आवादी प्रवासी है, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय हैं, इसलिए भारतीय अनाज, दाल और प्रोसेस्ड फूड की मांग लगातार बढ़ रही है। मध्यप्रदेश इस मांग को पूरा कर सकता है।

जहरीली शराब की मौतों पर हर बार कार्रवाई, पर जहर का राज अब भी बरकरार

आखिर शराब में मौत का कौन सा रसायन मिलाया जा रहा

भोपाल । मध्य प्रदेश में जहरीली शराब का कारोबार और इससे होने वाली मौतों कोई नई समस्या नहीं हैं। सागर में शनिवार को हुई दर्दनाक घटना ने एक बार फिर इस पुराने सवाल को सामने ला दिया है कि आखिर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला मौतों के बाद ही क्यों शुरू होता है ? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जहरीली शराब पीने से मौत की पुष्टि होने के बावजूद कई मामलों में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि आखिर शराब में कौन सा रसायन मिला था।

उज्जैन, मुरैना, मंदसौर और इंदौर में पिछले वर्षों में जहरीली शराब से सामूहिक मौतों की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। घटनाओं के बाद प्रशासनिक कार्रवाई हुई, आरोपी पकड़े गए, कहीं अधिकारियों को निलंबित किया गया तो कहीं आरोपियों की संपत्तियों पर कार्रवाई हुई। बावजूद इसके अवैध शराब की सप्लाई का नेटवर्क पूरी तरह खत्म नहीं हो सका। अब सागर की घटना के बाद एक बार फिर अवैध शराब के नेटवर्क के साथ-साथ आबकारी और प्रशासनिक व्यवस्था की निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं।जहरीली शराब से मौत की घटनाओं



में सबसे अहम सवाल यह होता है कि शराब में ऐसा क्या मिला था, जिससे लोगों की जान चली गई।

मध्य प्रदेश में सामने आए कई पुराने मामलों में शुरूआती जांच में डिनेचर्ड या मेथिलेटेड स्प्रिट जैसे पदार्थों का उल्लेख हुआ, लेकिन संबंधित रसायन की अंतिम और स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक स्तर पर सामने आने की जगह स्थिति हमेशा साफ नहीं रही। उज्जैन की 2020 की घटना इसका बड़ा उदाहरण रही। शुरूआती रिपोर्टों में मौतों की संख्या 12 से 14 बताई गई थी, जबकि बाद के न्यायिक रिकॉर्ड में 16 मौतों का

उल्लेख मिलता है। जांच में डिनेचर्ड/मेथिलेटेड स्प्रिट से संबंध की बात सामने आई और बाद में इथाइल व मिथाइल अल्कोहल के संकेतों का भी उल्लेख हुआ। मुरैना में जनवरी 2021 में छैरा और मनपुर गांवों में अवैध शराब पीने से 24 लोगों की मौत हुई थी। कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। इस मामले में आरोपियों को सजा भी हुई, लेकिन घटना के बाद भी यह सवाल बना रहा कि इस्तेमाल किए गए जहरीले मिश्रण की आधिकारिक पहचान और जानकारी आम लोगों तक कितनी स्पष्टता से पहुंची।

बैरिकेड तोड़कर फतेहगढ़ सडक पर बैठे डाक्टर

इंटरन डॉक्टरों का भोपाल में हल्लाबोल, स्टाइपेंड की मांग पर पुलिस से झड़प

भोपाल । मध्य प्रदेश में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे इंटरन डॉक्टरों का सन्न अब जवाब दे गया है। सरकार के कोरे आश्वासनों से नाराज होकर इंटरन डॉक्टरों ने सोमवार को राजधानी भोपाल में मोर्चा खोल दिया है। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री निवास की ओर मार्च निकाल रहे इंटरन डॉक्टरों को रोकने के दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान पुलिस और डॉक्टरों के बीच झड़प हुई। वाटर कैनन की चपेट में आने से एक छात्र के चोट लगने की जानकारी है। कुछ इंटरन डॉक्टरों ने हमीदिया अस्पताल का गेट और बैरिकेड तोड़ दिया। इसके बाद वे बाहर निकलकर फतेहगढ़ की मुख्य सडक पर



पहुंच गए और सडक पर बैठ गए। कुछ छात्र गेट तोड़कर बाहर जाते हुए भी दिखाई दिए।अपनी मांगों को लेकर वे चिकित्सक हमीदिया अस्पताल से सीधे मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच कर रहे हैं।

31 दिसंबर को रिटायर कर्मचारियों के सामने 8वें वेतन आयोग से बाहर होने का खतरा

रिटायरमेंट की एक तारीख बदल सकती है पेंशन का गणित

भोपाल । सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट की तारीख आमतौर पर महज एक प्रशासनिक औपचारिकता मानी जाती है, लेकिन 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के संदर्भ में यही 24 घंटे का अंतर हजारों कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर लंबे समय तक असर डाल सकता है। 31 दिसंबर 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों और 1 जनवरी 2026 को रिटायर होने वालों के बीच नए वेतनमान और पेंशन के लाभ को लेकर बड़ा अंतर बनने की आशंका है।कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यदि कटऑफ डेट में बदलाव नहीं किया गया तो 31 दिसंबर को रिटायर हुए कर्मचारी संभावित रूप से 8वें वेतन आयोग के लाभ से बाहर हो सकते हैं।मौजूदा व्यवस्था में पेंशन



रिटायरमेंट के समय निर्धारित वेतन के आधार पर तय होती है। ऐसे में 31 दिसंबर 2025 को सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन पुराने वेतनमान के आधार पर तय होने की स्थिति बन सकती है, जबकि अगले ही दिन यानी 1 जनवरी 2026 को

सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को संशोधित वेतनमान का लाभ मिल सकता है। यही अंतर आगे चलकर पेंशन की राशि में भी दिखाई देगा। कर्मचारी संगठनों की चिंता यह है कि एक बार पेंशन पुराने आधार पर तय होने के

बाद उसका प्रभाव केवल शुरूआती महीनों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि लंबे समय तक बना रह सकता है।इधे लाख कर्मचारियों पर असर की आशंका देश में करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 68 लाख पेंशनभोगी हैं। हर साल करीब 1.5 से 2 लाख केंद्रीय कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं। ऐसे में 31 दिसंबर 2025 को रिटायर हुए कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के दायरे में नहीं लाया गया तो बड़ी संख्या में कर्मचारी और उनके परिवार संभावित वित्तीय लाभ से बाहर हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी करीब एक लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं। इनमें रेलवे, आयकर, डाक और दूसरे केंद्रीय विभागों के कर्मचारी शामिल हैं।

बीज रियायती दर पर उपलब्ध करने की योजना है। उद्यानिकी संचालनालय ने प्याज-लहसुन क्लस्टर विकसित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। इसके साथ ही अलग-अलग जिलों को फल और फूलों के क्लस्टर विकसित करने का लक्ष्य भी दिया जाएगा। मंदिरों के आसपास फूल उत्पादन के विशेष क्लस्टर बनाए जाने की योजना है।सरकार की योजना का सबसे अहम हिस्सा फसल को खेत से सीधे मंडी तक भेजने के बजाय उत्सव क्लैव्यू

एडिशन करना है। इसके लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लगाने पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। इससे प्याज और लहसुन जैसी फसलों को लंबे समय तक उपयोग योग्य उत्पादों में बदला जा सकेगा। फल-सब्जियों से पल्प, पाउडर और फ्लेक्स जैसे उत्पाद तैयार कर उन्हें बड़े बाजारों और निर्यात बाजार तक पहुंचाने की कोशिश होगी। इस मॉडल का उद्देश्य यह है कि उत्पादन बढ़ ? के बाद यदि मंडी में कीमते गिरती हैं

भोपाल भाजपा की जिला

टीम में 90 नए चेहरे



भोपाल । भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल में जिला संगठन की नई टीम का ऐलान कर दिया है। रविवार देर रात करीब डेढ़ बजे जिला कार्यसमिति की सूची जारी की गई। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सहमति के बाद जिलाध्यक्ष रविंद्र यती ने सदस्यों के नामों की घोषणा की। नई कार्यसमिति में कुल 90 कार्यकर्ताओं को जिला कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है। इनमें मनोज राठीर, मनोज राजू अनेजा, राजेश खटीक, महेश जोशी, दिनेश पांडे, अनुषा सिंह रघुवंशी, पूजा भारद्वाज, विकास शर्मा (बंटी), सुमत कुमार जैन और सुनील व्यास समेत कई नेताओं को जगह मिली है।नई सूची में सबसे चर्चित नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी का है।

कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पचौरी को स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। इस श्रेणी में कुल 23 नेताओं को शामिल किया गया है। इनमें रघुनंदन शर्मा, पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता, विश्वास सागर, कृष्णा गौर, सांसद आलोक शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवान दास सबनानी, धुवनारायण सिंह, महापौर मालती राय, राहुल कोठारी और सुमित पचौरी समेत वरिष्ठ नेता शामिल हैं। स्थायी आमंत्रित सदस्यों की सूची में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ सरकार और संगठन से जुड़े प्रमुख चेहरों को जगह दी गई है।

प्याज-लहसुन की कीमतों के उतार-चढ़ाव पर सरकार का नया दांव

प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी

शहरों की मांग के हिसाब से फसल उत्पादन, क्लस्टर में किसानों को जोड़ा जाएगा; 2030 तक 30 लाख हेक्टेयर में उद्यानिकी का लक्ष्य



भोपाल । मध्य प्रदेश में प्याज-लहसुन समेत फल और सब्जियों के बाजार भाव में आने वाले उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए सरकार अब सिर्फ उत्पादन बढ़ाने पर निर्भर नहीं रहेगी। फसल के उत्पादन से लेकर उसकी प्रोसेसिंग, परिवहन और बड़े बाजार तक पहुंच बनाने के लिए क्लस्टर आधारित मॉडल तैयार किया जा रहा है। इसके तहत प्याज और लहसुन के विशेष क्लस्टर विकसित किए जाएंगे और किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले

बीज रियायती दर पर उपलब्ध करने की योजना है। उद्यानिकी संचालनालय ने प्याज-लहसुन क्लस्टर विकसित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। इसके साथ ही अलग-अलग जिलों को फल और फूलों के क्लस्टर विकसित करने का लक्ष्य भी दिया जाएगा। मंदिरों के आसपास फूल उत्पादन के विशेष क्लस्टर बनाए जाने की योजना है।सरकार की योजना का सबसे अहम हिस्सा फसल को खेत से सीधे मंडी तक भेजने के बजाय उत्सव क्लैव्यू

एडिशन करना है। इसके लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लगाने पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। इससे प्याज और लहसुन जैसी फसलों को लंबे समय तक उपयोग योग्य उत्पादों में बदला जा सकेगा। फल-सब्जियों से पल्प, पाउडर और फ्लेक्स जैसे उत्पाद तैयार कर उन्हें बड़े बाजारों और निर्यात बाजार तक पहुंचाने की कोशिश होगी। इस मॉडल का उद्देश्य यह है कि उत्पादन बढ़ ? के बाद यदि मंडी में कीमते गिरती हैं